भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 491
उत्तर देने की तारीख 20 नवम्बर, 2019

राजस्थान के सुदूर गांवों में इंटरनेट सुविधा

491. श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान राज्य के सुदूर गांवों में इंटरनेट सुविधा नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या जिन गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है वहां इंटरनेट/ब्रॉडबैंड की गति बहुत धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 की ''भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक'' रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रति 100 की आबादी पर 28.66 ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता हैं। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ अधिसूचित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी के लिए ब्रॉडबैंड की व्यवस्था करना शामिल है।

(ख) और (ग) इंटरनेट की गति अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मानकों जैसे प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, नेटवर्क कवरेज पर एक साथ एक्सेस करने वाले उपयोगकर्त्ताओं की संख्या, एक्सेस की जा रही वेबसाइट की कनेक्टिविटी आदि पर निर्भर करती है। मोबाइल इंटरनेट की गति आगे कई कारकों जैसे उपभोक्ताओं को सेवा दे रहे बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) से दूरी, बीटीएस द्वारा दी जा रही सेवा का एक साथ उपयोग करने वाले उपयोगकर्त्ताओं की संख्या, बीटीएस द्वारा हैंडल किया जा रहा ट्रैफिक आदि पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मोबाइल के

उपयोगकर्त्ताओं को उपयोग के अलग-अलग स्थानों और समय पर इंटरनेट की अलग-अलग गति का अनुभव हो सकता है।

(घ) सरकार द्वारा ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं की व्यवस्था करने तथा उसे बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित पहल/कार्रवाई की गई है:-

i) भारतनेट के तहत राजस्थान सहित देश के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। दिनांक 07.11.2019 की स्थिति के अनुसार बीएचक्यू सहित कुल 10,070 ग्राम पंयायतो में से 8683 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

ii) भारतनेट परियोजना के हिस्से के तौर पर ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं के एक्सेस के लिए वाई-फाई या किसी दूसरे उपयुक्त ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम छोर की कनेक्टिविटी राजस्थान सहित देश के सभी ग्राम पंचायतों को प्रदान की जा रही है। राजस्थान के 10,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की व्यवस्था का कार्य राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राजकॉम्प इन्फो सर्विस लि. (आरआईएसएल) द्वारा किया जा रहा है।

iii) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के टेलीफोन एक्सचेंजों की अवसंरचना का इस्तेमाल करके राजस्थान में 1645 सहित 25,00 सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पाटों की स्थापना के लिए एक स्कीम का वित्तपोषण कर रहा है।

****